



2026:AHC:166658-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट टैक्स संख्या - 3402/2026

मो. कमर

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: अनिल प्रकाश माथुर

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 39

माननीय न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह

माननीय न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल प्रकाश माथुर और राज्य के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार मिश्रा को सुना गया।
2. सहायक आयुक्त, राज्य कर, सेक्टर-7, मुरादाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.07.2026 को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।
3. अभिवेदन प्रस्तुत किए गए हैं कि रद्दीकरण की उपरोक्त कार्रवाई अवैध है। कारण बताओ नोटिस दिनांक 02.07.2026 के माध्यम से उठाए गए सभी तथ्यात्मक आधारों का याचिकाकर्ता द्वारा अपने लिखित उत्तर के माध्यम से स्पष्ट रूप से उत्तर दिया गया था। यद्यपि उस उत्तर को अभिलेख पर लिया गया है, रद्दीकरण का आदेश दिनांक 17.07.2026 उन आपत्तियों पर विचार नहीं करता है। जहां तक अलग मार्ग से यात्रा कर रहे माल का संबंध है, यह स्पष्ट किया गया है कि परिवहन वाहनों द्वारा अपनाए जाने के लिए कोई एक विहित मार्ग मौजूद नहीं है। जिस सीमा तक, यह अनुमान लगाने के लिए कोई ठोस सामग्री मौजूद नहीं रही होगी कि याचिकाकर्ता ने

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



माल के साथ किसी भी अन्य तरीके से व्यवहार किया था, जो कि अनुमत था, पंजीकरण रद्द करना अनुमन्य नहीं है।

4. आगे, यह पुरजोर आग्रह किया गया है कि पंजीकरण रद्द करने से व्यवसाय बंद होने का प्रभाव पड़ा है। यहां, कोई न्यायनिर्णयन आदेश पारित नहीं किया गया है और कर की कोई पक्की मांग मौजूद नहीं है, फिर भी याचिकाकर्ता के व्यवसाय पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि पंजीकरण रद्द होने पर, सभी व्यावसायिक संचालन बंद कर दिए गए हैं। इसलिए, इस न्यायालय द्वारा रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप आवश्यक है।

5. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि तथ्य संबंधी मुद्दे शामिल हैं। आक्षेपित आदेश को रद्द करने की मांग करके यूपीजीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 30 के अंतर्गत और उचित वैधानिक अपील दाखिल करके अधिनियम की धारा 107 के अंतर्गत याचिकाकर्ता को वैधानिक उपचार उपलब्ध हैं।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि तथ्य संबंधी मुद्दे शामिल हैं। पक्के निष्कर्ष निकाले जा सकने से पहले उनके लिए साक्ष्य की जांच की आवश्यकता होगी। हम जानबूझकर मुख्य रूप से यूपीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 21(ई) के उल्लंघन जैसे सटीक विवादों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह वैधानिक उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इस प्रकार अधिनियम की धारा 16 के उल्लंघन में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने का आरोप पंजीकरण रद्द करने का आधार है। यहां, राजस्व के विद्वान अधिवक्ता ने यूपीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 21(ई) के साथ पठित धारा 29(2)(ए) पर भरोसा किया है। अधिनियम और नियमावली के उन प्रावधानों की वैधता को कोई चुनौती नहीं दी गई है।

7. इसलिए, हमारे लिए यह जांचने का कोई अवसर नहीं है कि क्या आईटीसी का गलत लाभ उठाने के कारण पंजीकरण रद्द किया गया है।

8. जिस सीमा तक आईटीसी का गलत लाभ उठाने का आरोप मौजूद है और आगे चूंकि यह मुद्दा तथ्यात्मक है, हम इसे वैधानिक प्राधिकारी पर छोड़ देते हैं कि वह इससे निपटे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. जहां तक वैधानिक उपचारों का संबंध है, निर्विवाद रूप से दो हैं- याचिकाकर्ता या तो आक्षेपित आदेश को रद्द करने की मांग कर सकता है या उसके विरुद्ध अपील दाखिल कर सकता है या पहले रद्दीकरण की मांग कर सकता है और उसके पश्चात अपील दाखिल कर सकता है।

10. उस प्रकाश में देखा जाए तो, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपनी असाधारण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि आक्षेपित आदेश को जन्म देने वाले कारण बताओ नोटिस जारी करने में कोई अंतर्निहित क्षेत्राधिकार संबंधी दोष नहीं है और आगे चूंकि याचिकाकर्ता ने अपना उत्तर दाखिल किया था जिस पर विचार किया गया होगा। इस प्रकार, रद्दीकरण और अपील के वैधानिक उपचार के सामने, दावा किए गए हस्तक्षेप से इनकार किया जाता है।

11. हालांकि वाद के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता में और प्रस्तुत किए गए अभिवेदनों को स्वीकार करते हुए कि पंजीकरण रद्द करने के गंभीर परिणाम होते हैं, हम यह प्रावधान करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा आज से तीन दिनों की अवधि के भीतर पंजीकरण रद्द करने के लिए उचित प्रार्थना पत्र दाखिल करने के अधीन, याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात, वहां से दस दिनों की अवधि के भीतर एक सकारण और स्पष्ट आदेश द्वारा, उस प्रार्थना पत्र पर उसके अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है और निर्णय लिया जा सकता है।

12. उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी) (न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह)

10 अगस्त, 2026

शिव

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”